

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के सफल कार्यान्वयन हेतु दिनांक-23.09.2019 मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (SLSMC) की 17^{वीं} बैठक की कार्यवाही।

अनुपस्थिति :- संलग्न

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) झारखण्ड राज्य में जून, 2015 से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष-2022 तक सभी आवास विहीन शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) राज्य के सभी शहरी निकायों में क्रियान्वित है।

योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति State Level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC) की 17^{वीं} बैठक में निम्न प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया :-

प्रस्ताव सं० 1 -गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई। (परिशिष्ट "क")

प्रस्ताव सं० 2 - योजना के चतुर्थ घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" हेतु राज्य के 17 शहरी स्थानीय निकायों के 8374 आवासों के निर्माण हेतु निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) भारत सरकार को भेजने हेतु अनुमोदन।

योजना के चतुर्थ घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 (Ph-II) में राज्य के 17 शहरी स्थानीय निकायों के 8374 आवासों के निर्माण हेतु निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) प्राप्त हुये हैं, जिस पर State Level Appraisal Committee (SLAC) का अनुमोदन प्राप्त है। प्रस्तावित 8374 आवासों के निर्माण की कुल परियोजना राशि 30322.25 लाख रुपये है।

निकायवार लाभकों की संख्या एवं अंशदान की विवरणी निम्नवत् है:-

Sl. No.	ULB	No. of Beneficiary	Central Share @ Rs.1.5 Lakh	State Share @ Rs. 0.75 Lakh	Beneficiaries' Contribution @ Rs. 1.371 Lakh	Total Project Cost (in Lakhs)	Unit Cost per DU (in Lakhs)
1	Chhatarpur	790	1185.00	592.50	1083.09	2860.59	3.621
2	Deoghar	1295	1942.50	971.25	1775.445	4689.20	
3	Godda	689	1033.50	516.75	944.62	2494.87	
4	Madhupur	200	300.00	150.00	274.20	724.20	
5	Mango	16	24.00	12.00	21.936	57.94	
6	Majhiaon	309	463.50	231.75	423.639	1118.89	
7	Ramgarh	10	15.00	7.50	13.71	36.21	
8	Chas	450	675.00	337.5	616.95	1629.45	
9	Seraikela	21	31.50	15.75	28.791	76.04	
10	Gumla	350	525.00	262.50	479.85	1267.35	
11	Hussainabad	208	312.00	156.00	285.17	753.17	
12	Giridih	3029	4543.50	2271.75	4152.76	10968.01	
13	Rajmahal	48	72.00	36.00	65.81	173.81	
14	Dumka	296	444.00	222.00	405.82	1071.82	
15	Basukinath	25	37.50	18.75	34.28	90.53	
16	Jhumritelaiya	443	664.50	332.25	607.35	1604.10	
17	Bundu	195	292.50	146.25	267.35	706.10	
Total		8374	12561.00	6280.5	11480.75	30322.25	

अतः लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7C) पर वांछित सूचना के साथ-साथ DPRs भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाने हेतु समिति का अनुमोदन दिया गया।

2649
24/10/19

प्रस्ताव सं० 3 – PMAY(U) के प्रथम घटक 'स्व स्थाने स्लम पुनर्विकास' (ISSR) अन्तर्गत राज्य के विभिन्न निकायों के परियोजनाओं हेतु स्वीकृत DPRs, के संशोधन पर अनुमोदन।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम घटक "स्व स्थाने स्लम पुनर्विकास" अन्तर्गत राज्य के विभिन्न निकायों के कुल 15517 आवासीय परियोजनाएं (G+4 प्रारूप पर) की स्वीकृति भारत सरकार की विभिन्न CSMC बैठकों में प्राप्त की गयी थी।

योजना के प्रथम घटक के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या-5381 दिनांक-02.11.2018 निर्गत किया गया है साथ ही परियोजना अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हित की गयी थी, किन्तु उक्त भूमियों के सीमांकन/हस्तांतरण के क्रम में उपलब्ध भूमि में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी हुई है। फलस्वरूप परियोजनाओं के DPRs निम्न बिन्दुओं के आधार पर संशोधित किया गया है –

- आवास का निर्माण G+3/G+6/ G+8 के Model में किया जाना है जो कि पूर्व से स्वीकृत DPR, G+4 प्रारूप पर था जिसमें लिफ्ट का प्रावधान नहीं था।
- कुल स्लम पुनर्विकास परियोजना भूमि के 50% हिस्से पर किए जाने तथा 50% भूमि सफल विकासकर्ता को आवंटित किए जाने का प्रावधान था जिसे बदलकर कुल स्लम पुनर्विकास परियोजना भूमि का 55% पर स्लम का पुनर्विकास किया जाएगा एवं 45% भूमि सफल विकासकर्ता को आवंटित किए जाने का प्रावधान किया गया ताकि अधिक से अधिक विकासकर्ता परियोजनाओं के निर्माण में भाग ले सकें।

योजनाओं की कुल तकनीकी अनुमोदित राशि 53876.96/- (पांच सौ अड़तीस करोड़ छिहत्तर लाख छियानबे हजार रुपये) मात्र है, जिस पर मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी। संशोधित परियोजना विवरणी निम्नवत् है :-

ULB	Project Location	पूर्व में G+4 प्रारूप पर स्वीकृत DUs की विवरणी						वर्तमान में G+3/ G+6/ G+8 प्रारूप पर प्रस्तावित DUs						
		CSMC No.	Sanctioned DUs	EWS Area	Deve loper Area	Project Cost	Project Location	DUs Proposed	EWS Area	Deve loper Area	Project Cost	Cost / DU	Model	Insitu/Relocation
				Acres	Acres				Acres	Acres				
Gumla	Chetar	29 th	75	0.66	0.66	813.00	Chetar	75	0.72	0.58	566.59	7.55	G+3	Rel
Khunti	Jamwadag	29 th	420	2.29	2.29	3835.00	Jamwadag	360	2.40	1.96	2599.29	7.22		
Hazaribgh	Gadikhana	29 th	220	1.25	1.25	5649.00	Gadikhana	128	0.73	0.59	1081.24	8.45	G+8	Insitu
Chakradh arpur	Harijan Basti	34 th	48	0.30	0.30	1137.29	Harijan Basti	60	0.32	0.28	466.30	7.77		
Chakulia	Hatchali & Sugribasa	34 th	180	0.90	0.90	3724.30	Hatchali & Sugribasa	200	0.99	0.81	1385.64	6.93	G+3	Rel
Pakur	Devpur	34 th	260	1.83	1.83	4192.99	Devpur	160	1.82	1.49	1130.12	7.06		
Deoghar	Hardlakund	34	700	4.84	4.84	11103.10	Hardlakund	100	0.96	0.79	717.95	7.18		
	Sundari													
Garhwa	Sonpurwa	29 th	160	1.00	1.00	4006.00	Sonpurwa	120	1.10	0.90	830.82	6.92	G+6	Rel
Ranchi	Anni	29 th	8720	45.25	45.25	190760.0	Tirl	2119	13.17	10.78	21016.34	9.92		
							Labd	2401	14.89	12.20	24082.67	10.03		
			10783			225220.68		5723			53876.96			

अतः "स्व स्थाने स्लम पुनर्विकास" हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7A) पर वांछित सूचना के साथ-साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाने हेतु समिति का अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव सं० 4 — डोमचांच नगर पंचायत अंतर्गत PMAY(U) के चतुर्थ घटक के तहत स्वीकृत DPR के 7C के संशोधित पर अनुमोदन।

डोमचांच नगर पंचायत अंतर्गत PMAY(U) के DPR (1018 लाभुक) की स्वीकृत भारत सरकार की 44वीं CSMC (दिनांक-28.06.2019) में प्राप्त हुई थी। स्वीकृत DPR के Annexure 7C में लाभुकों के वर्गीकरण में संशोधन हेतु निकाय से अनुरोध किया गया है जिसका वर्गीकरण निम्नवत् है :-

CSMC	Male	Female	Total	Gen	SC	ST	OBC	Minority
44 th CSMC बैठक में स्वीकृत 7C के अनुरूप वर्गीकरण	712	306	1018	134	100	02	782	26
संशोधित 7C का वर्गीकरण	280	738	1018	130	93	02	793	28

अतः उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर संशोधित 7C भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाने हेतु समिति का अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव सं० 5 — PMAY(U) के प्रथम घटक "स्व स्थाने स्लम पुनर्विकास" के तहत राज्य के हुसैनाबाद शहरी स्थानीय निकाय के 300 आवासों के निर्माण हेतु नये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) भारत सरकार को भेजने हेतु अनुमोदन।

योजना के प्रथम घटक "स्व स्थाने स्लम पुनर्विकास" अन्तर्गत राज्य के नगर निकाय हुसैनाबाद क्षेत्राधीन कुल 300 नये आवासों के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) JUIDCO Ltd. से प्राप्त हुई है। उक्त DPR पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान की गयी एवं State Level Appraisal Committee (SLAC) का अनुमोदन प्राप्त है।

प्रस्तावित परियोजनाओं अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राशि 1 लाख रुपये प्रति आवास होगी, राज्यांश की राशि 1 लाख रुपये प्रति आवास तथा शेष लाभुक 1.5 लाख अंशदान होगा। योजनाओं की कुल तकनीकी अनुमोदित राशि 2035.10 /- (बीस करोड़ पैंतीस लाख दस हजार रुपये) मात्र है, परियोजना विवरणी निम्नवत् है:-

ULB	Project Location	Dus proposed	EWS Area	Developer Area	Project Cost (in Rs. Lakhs)	Model
			Acres	Acres		
Hussainabad	Japla Choubey	300	2.20	1.80	2035.10	G+3

भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7A) पर वांछित सूचना के साथ-साथ निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव सं० 6 — योजना के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण" हेतु राज्य के 2 शहरी स्थानीय निकायों के 140 आवासों के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के संशोधन हेतु अनुमोदन।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक अन्तर्गत मिहिजाम एवं जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र के कुल 160 आवासों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार की 34th CSMC की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

योजना कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प- 5382, दिनांक-02.11.2018 निर्गत किया गया है, साथ ही परियोजना अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हित की गयी थी, किन्तु उक्त भूमियों के सीमांकन/हस्तांतरण के क्रम में उपलब्ध भूमि में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी हुई है।

फलस्वरूप तृतीय घटक के तहत स्वीकृत परियोजना को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है। योजनाओं की कुल तकनीकी अनुमोदित राशि 11,47,89,000/- (ग्यारह करोड़ सैतालिस लाख नवासी हजार रुपये) मात्र है, जिस पर मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-301, दि०-11.03.2015 के आलोक में समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी। संशोधित परियोजना विवरणी निम्नवत् है :-

(in Rs. Lakhs)

ULB	पूर्व में G+4 प्रारूप पर स्वीकृत DUs की विवरणी					वर्तमान में G+3/ G+6/ G+8 प्रारूप पर प्रस्तावित DUs					
	Project Location	CSMC No.	Sanctioned DUs	Project Area	Project Cost	DUs Proposed	EWS Area	Project Cost	Cost / DU	Model	Community Centre
				(Acres)			Acres				
Mihijam	Kangoi (Leprsy Colny)	34 th	64	1.00	599.20	60	1.00	550.80	9.18	G+1	Outside
Jugsalai	Harijan Basti		96	0.53	719.34	80	0.53	597.09	7.46	G+3	Outside
Total			160		1319.0	140		1147.89			

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7B) पर वांछित सूचना के साथ-साथ DPRs भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव 7- राजीव आवास योजना अन्तर्गत चास नगर निगम के माझीडीह में निर्मित 128 आवास, (G+4 प्रारूप पर) के आवंटन हेतु अनुमोदन।

चास नगर निगम के माझीडीह अन्तर्गत कुल 128 आवास, (G+4 प्रारूप पर) राजीव आवास योजना अन्तर्गत निर्मित हैं जिनमें से 44 आवासों का आवंटन राष्ट्रीय राजमार्ग-32 चौथीकरण के दरमियान 44 विस्थापित योग्य लाभुकों को किया जा चुका है। शेष 84 आवासों का आवंटन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक/प्रथम घटक के तहत योग्य लाभुकों को किये जाने के संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव संचिका के माध्यम से सभी विवरणी सहित अनुमोदन हेतु अलग से प्रेषित की जाए।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाई सम्पन्न की गई।

कार्यवाही पर ना. प्रमुख के अनुमोदन 26/10/19

(डी० के० तिवारी)

सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:- 07/न०प्र०नि०/PMAY(HFA)/01/2015.26.10.19 राँची/दिनांक:24/10/19

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड के प्रधान आर्वा सचिव/बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।